पटना उच्च न्यायालय के अधिकारिता में

2023 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 519
2020 का दीवानी समीक्षा संख्या 21

==========

1. कुमार गौरव सिंह, पुत्र- कौशल किशोर सिंह, निवासी-गाँव-शाहजहांपुर, थाना-शाहजहांपुर, जिला पटना, अनुक्रमांक 21506672
2. अरविंद कुमार, पुत्र- गुलशन राय, निवासी-गाँव-पंचबीरिया, थाना- गरखा, जिला- सारण, छपरा, अनुक्रमांक 21508143
3. सूर्य प्रकाश निराला, पुत्र- दिनेश प्रसाद, निवासी-गाँव-अब्दलपुर, थाना- वारिसलीगंज, जिला नवादा, अनुक्रमांक 21502278
4. विकास कुमार, पुत्र- उमेश प्रसाद, निवासी- रक्सौल, थाना- रक्सौल, जिला पूर्वी चंपारण, अनुक्रमांक 21510979
5. अभिनंदन कुमार, पुत्र- शंभू प्रसाद, निवासी-गाँव- मथियां, थाना- लौरिया, जिला- पश्चिम चंपारण, अनुक्रमांक 21503774
6. रजनीकांत सक्सेना, पुत्र- सरोज कुमार, निवासी-गाँव-गौरव नगर, थाना.-परवलपुर, जिला-नालंदा, अनुक्रमांक 21505864
7. संजीव कुमार, पुत्र- राज कुमार साह निवासी-गाँव-मणियारपुर, थाना- बरिश नगर, जिला समस्तीपुर, अनुक्रमांक 21500802
8. राकेश कुमार सिंह, पुत्र-स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, निवासी-गाँव-नवतोइला, जमालपुर रोड, थाना-कासिम बाजार, जिला-मुंगेर, अनुक्रमांक -21511817
9. श्याम बाबू कुमार, पुत्र- राजेंद्र प्रसाद, निवासी-गाँव-मुशसनिया, थाना-सोनवर्षा, जिला-सीतामढ़ी, अनुक्रमांक-21511662
10. नितीश कुमार, पुत्र-ज्ञान चंद भगत, निवासी-गाँव-परवता, थाना-परवता, जिला-खगड़िया, अनुक्रमांक-2150914
11. सुधीर कुमार, पुत्र- साधुशरण प्रसाद, निवासी-गाँव-समाबाद, थाना- रहुई, जिला-नालंदा, अनुक्रमांक 21510431

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना अपने सचिव के माध्यम से।
2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के अध्यक्ष।
3. सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

4. शशि भूषण सिंह, पुत्र-श्याम मोहन सिंह, निवासी-गाँव-सकरी, थाना-कुदरा, जिला-कैमूर भभुआ, अनुक्रमांक-21514540
5. संतोष कुमार, पुत्र- कृष्णदेव प्रसाद, निवासी-गाँव-पंसलवा, थाना-बेलदौर, जिला-खगड़िया, अनुक्रमांक-21511091
6. चंद्र किशोर कुमार, पुत्र- सुरेश मेहता, निवासी-गाँव-देपुरा, थाना-ग्वालपारा, जिला-मधेपुरा, अनुक्रमांक-21514166
7. विजय शंकर कुमार, पुत्र- शिव नाथ यादव, निवासी-गाँव-तेलकाथू, थाना-एम. एच. नगर, हसनपुरा, जिला-सिवान, अनुक्रमांक-21511298
8. बिहार राज्य।
9. निदेशक, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना।
10. निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, कृषि विभाग, पटना।
11. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना।

.... उत्तरदातागण

==========

के साथ

2023 का पत्र पेटेंट अपील सं. 520

में

2020 का दीवानी समीक्षा संख्या 19

==========

1. नवनीत कुमार, पुत्र- स्वर्गीय भागवत प्रसाद, निवासी-गाँव-रतनपुरा, थाना-इशलामपुर, जिला-नालंदा, अनुक्रमांक 21508391
2. चंदन कुमार, पुत्र- हीरालाल प्रसाद, निवासी-मोहल्ला-पूसा बाजार, पूसा, थाना-पूसा, जिला समस्तीपुर,अनुक्रमांक 21504788
3. सुरेश कुमार, पुत्र- गणेश सिंह, निवासी-गाँव-भूप भैरो, थाना-सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी, अनुक्रमांक 21503865
4. विजय कुमार, पुत्र-अशरफी रे, निवासी-गाँव-खपुरा के निवासी, डाकघर और थाना-खानपुर पाकरी, जिला-वैशाली, अनुक्रमांक 21511011
5. बिपिन कुमार, पुत्र- मथुरा प्रसाद, निवासी-गाँव-खाखरा, थाना-शेखपुरा, जिला-शेखपुरा, अनुक्रमांक 21512292
6. ललन कुमार, पुत्र- मुंड्रिका प्रसाद यादव, निवासी-गाँव- जैनगर बारी कवैगा, थाना-लखीसराय, जिला-लखीसराय, अनुक्रमांक 21504710
7. शशि भूषण कुमार, पुत्र- माधव प्रसाद यादव, निवासी-गाँव-राही जगतपुर, थाना-लक्ष्मीपुर लालचंद, जिला-मधेपुरा, अनुक्रमांक 21502683

8. रविंदर कुमार, पुत्र-वकील सिंह निवासी-गाँव-राजपुर, थाना-राजपुर, जिला-रोहतास, अनुक्रमांक-21505435 ।
9. संजय कुमार, पुत्र-स्वर्गीय श्याम किशोर सिंह, निवासी-गाँव -महथिन तोला, डाकघर और थाना-बालिगिरवन, जिला भोजपुर, अनुक्रमांक 21504660
10. नंदन सिंह, पुत्र- जवाहर सिंह, निवासी-गाँव-जमुराहा, थाना-रामगढ़, जिला कैमूर, अनुक्रमांक 21502502
11. सुशील कुमार यादव, पुत्र-दीपक कुमार निवासी-गाँव कुशाहा, डाकघर- कमलदह, थाना-किशनपुर, जिला सुपौल, अनुक्रमांक 21506290
12. अंशु कुमार, पुत्र-आनंद शिव नारायण सिंह, निवासी-गाँव-रतनपुर, थाना-बरियारपुर, जिला मुंगेर, अनुक्रमांक 21503758
13. कुमार बीरेंद्र सिंह, पुत्र- नवल किशोर सिंह, निवासी-गाँव-शेरपुर, डाकघर नेहुसा, थाना-हरनौत, जिला नालंदा, अनुक्रमांक-21508055
14. उमेश प्रसाद सिंह, पुत्र- स्वर्गीय भागवत सिंह, निवासी- गाँव-बिशुनपुर बेदौलिया, थाना-जंदाहा, जिला-वैशाली, अनुक्रमांक- 21509314
15. धनंजय कुमार यादव, पुत्र-सुरेश यादव, निवासी-आजाद नगर के निवासी, रोड संख्या-3 थाना कंकडबाग, जिला- पटना, अनुक्रमांक 21510343

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना अपने सचिव के माध्यम से।
2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के अध्यक्ष।
3. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के सचिव।
4. हंसराज हंस, पुत्र- रामसेवक सिंह, निवासी-गाँव-सोमनाहा मठ, थाना-पूसा, जिला-समस्तीपुर, अनुक्रमांक 21513082
5. मनोज कुमार, पुत्र- राम बदन चौधरी, निवासी-गाँव- गमरियां, थाना-नोखा, जिला-रोहतास, अनुक्रमांक 21512974
6. अमित कुमार, पुत्र- अशोक कुमार चकरवती, निवासी-गाँव रामदिहा, थाना-राहुई, जिला नालंदा, अनुक्रमांक 21510622
7. मनोज कुमार अकेला, पुत्र- राजेंद्र प्रसाद अकेला, निवासी-गाँव- नानंद, थाना-सिलाव, जिला नालंदा, अनुक्रमांक 21509910
8. अभिषेक प्रसाद, पुत्र- प्रदीप कुमार साह, निवासी-गाँव-हाफला गंज, डाकघर, थाना सिरनिया, जिला कटिहार, अनुक्रमांक 21504108
9. अमित कुमार, पुत्र-स्वर्गीय भारत भूषण प्रसाद, निवासी-गाँव जलालपुर, थाना-सोहसराय, जिला नालंदा, अनुक्रमांक 21500334

10. आनंद कुमार, पुत्र- राम बदन प्रसाद निवासी- सेंट्रल रेवेन्यू कॉलोनी, टाइप-**III**, क्वार्टर प्र. सं. 49, थाना-दीघा, जिला पटना, अनुक्रमांक 21513795
11. बिपू कुमार प्रसाद, पुत्र- हरहंगी प्रसाद, निवासी-गाँव- तिवारी चापड़ा, डाकघर, थाना भथवा.जिला- गोपालगंज, अनुक्रमांक 21500029
12. स्वर्ण किरण कुमार, पुत्र- नवल किशोर प्रसाद, निवासी-गाँव- केवल बीघा, घंघ, डाकघर, थाना सैस्तापुर, जिला पटना, अनुक्रमांक 21501110
13. रवि कुमार, पुत्र- शंकर लाल साह, निवासी- दुर्गा स्थान कस्बा, थाना-कस्बा, जिला-पूर्णिया, अनुक्रमांक 21502813
14. निशांत कुमार, पुत्र- मथुरा प्रसाद केशरी, निवासी- ग्राम- मधुबानी बाजार, प्रेमा इलेक्ट्रिकल, थाना- के. हाट जिला-पूर्णिया, पूरब, अनुक्रमांक 21510378
15. सुरेश गिरि, पुत्र- स्वर्गीय बिंदेश्वरी गिरी, निवासी-गाँव-खुशारा, थाना-कल्याणपुर, जिला-पूर्वी चंपारण, अनुक्रमांक 21510495
16. चंद्रशेखर कुमार, पुत्र- भिखारी महतो, निवासी-गाँव- राजवाड़ा बिरता, डाकघर मुशामिया, वाया सोनबरसा, थाना-मुशरनिया, जिला सीतामढ़ी
17. निदेशक, कृषि, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
18. निदेशक, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना।
19. निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, कृषि विभाग, पटना।
20. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना।

.... उत्तरदातागण

==========

संदर्भित मामलेः

- रितेश आर. साह बनाम वाई. एल. यमुल (डॉ.), (1996) 3 एस. सी. सी. 253,
- त्रिपुरारी शरण बनाम रंजीत कुमार यादव, (2018) 2 एससीसी 656
- देग वेंकट हर्ष वर्द्धन बनाम अकुला वेंकट हर्षवर्धन, (2019) 12 एस. सी. सी. 735
- भारत संघ बनाम रमेश राम (2010) 7 एससीसी 234
- आलोक कुमार पंडित बनाम असम राज्य (2012) 13 एस. सी. सी. 516
- इंद्र साहनी बनाम भारत संघ; 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217

एल. पी. ए.-सरकार की आरक्षण नीति को चुनौती देने के परिणामस्वरूप मेधावी आरक्षित उम्मीदवारों को उनकी पसंद के जिले दिए जाते हैं; केवल उनकी उच्च योग्यता के कारण सक्षम किया गया, जिसके परिणामस्वरूप परिणामी रिक्तियों में मेधावी सामान्य उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए आरक्षित उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया।

माना गया- रमेश राम मामले में सिद्धांत लागू नहीं होगा और रितेश आर.साह मामले और त्रिपुरारी शरण मामले में जो सिद्धांत है वह वर्तमान मामले में भी लागू होगा। (पैरा 25)

'एमआरसी' उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए जिलों में स्थानांतरित करने से बनी 93 रिक्तियां उन आरक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरी जानी चाहिए, वे उन वैकल्पिक जिलों में अव्यवस्थित हो जाएंगे जहां उन्हें नियुक्त किया गया था। (पैरा 26)

न्यायालय द्वारा अपीलें स्वीकृत (पैरा 27)

पटना उच्च न्यायालय के अधिकारिता में

2023 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 519
2020 का दीवानी समीक्षा संख्या 21

==========

1. कुमार गौरव सिंह, पुत्र- कौशल किशोर सिंह, निवासी-गाँव-शाहजहांपुर, थाना-शाहजहांपुर, जिला पटना, अनुक्रमांक 21506672
2. अरविंद कुमार, पुत्र- गुलशन राय, निवासी-गाँव-पंचबीरिया, थाना- गरखा, जिला- सारण, छपरा, अनुक्रमांक 21508143
3. सूर्य प्रकाश निराला, पुत्र- दिनेश प्रसाद, निवासी-गाँव-अब्दलपुर, थाना- वारिसलीगंज, जिला नवादा, अनुक्रमांक 21502278
4. विकास कुमार, पुत्र- उमेश प्रसाद, निवासी- रक्सौल, थाना- रक्सौल, जिला पूर्वी चंपारण, अनुक्रमांक 21510979
5. अभिनंदन कुमार, पुत्र- शंभू प्रसाद, निवासी-गाँव- मथियां, थाना- लौरिया, जिला- पश्चिम चंपारण, अनुक्रमांक 21503774
6. रजनीकांत सक्सेना, पुत्र- सरोज कुमार, निवासी-गाँव-गौरव नगर, थाना.-परवलपुर, जिला-नालंदा, अनुक्रमांक 21505864
7. संजीव कुमार, पुत्र- राज कुमार साह निवासी-गाँव-मणियारपुर, थाना- बरिश नगर, जिला समस्तीपुर, अनुक्रमांक 21500802
8. राकेश कुमार सिंह, पुत्र-स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, निवासी-गाँव-नवतोइला, जमालपुर रोड, थाना-कासिम बाजार, जिला-मुंगेर, अनुक्रमांक -21511817
9. श्याम बाबू कुमार, पुत्र- राजेंद्र प्रसाद, निवासी-गाँव-मुशसनिया, थाना-सोनवर्षा, जिला-सीतामढ़ी, अनुक्रमांक-21511662
10. नितीश कुमार, पुत्र-ज्ञान चंद भगत, निवासी-गाँव-परवता, थाना-परवता, जिला-खगड़िया, अनुक्रमांक-2150914
11. सुधीर कुमार, पुत्र- साधुशरण प्रसाद, निवासी-गाँव-समाबाद, थाना- रहुई, जिला-नालंदा, अनुक्रमांक 21510431

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना अपने सचिव के माध्यम से।
2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के अध्यक्ष।
3. सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

4. शशि भूषण सिंह, पुत्र-श्याम मोहन सिंह, निवासी-गाँव-सकरी, थाना-कुदरा, जिला-कैमूर भभुआ, अनुक्रमांक-21514540
5. संतोष कुमार, पुत्र- कृष्णदेव प्रसाद, निवासी-गाँव-पंसलवा, थाना-बेलदौर, जिला-खगड़िया, अनुक्रमांक-21511091
6. चंद्र किशोर कुमार, पुत्र- सुरेश मेहता, निवासी-गाँव-देपुरा, थाना-ग्वालपारा, जिला-मधेपुरा, अनुक्रमांक-21514166
7. विजय शंकर कुमार, पुत्र- शिव नाथ यादव, निवासी-गाँव-तेलकाथू, थाना-एम. एच. नगर, हसनपुरा, जिला-सिवान, अनुक्रमांक-21511298
8. बिहार राज्य।
9. निदेशक, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना।
10. निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, कृषि विभाग, पटना।
11. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना।

.... उत्तरदातागण

==========

के साथ

2023 का पत्र पेटेंट अपील सं. 520

में

2020 का दीवानी समीक्षा संख्या 19

==========

1. नवनीत कुमार, पुत्र- स्वर्गीय भागवत प्रसाद, निवासी-गाँव-रतनपुरा, थाना-इशलामपुर, जिला-नालंदा, अनुक्रमांक 21508391
2. चंदन कुमार, पुत्र- हीरालाल प्रसाद, निवासी-मोहल्ला-पूसा बाजार, पूसा, थाना-पूसा, जिला समस्तीपुर,अनुक्रमांक 2150-4788
3. सुरेश कुमार, पुत्र- गणेश सिंह, निवासी-गाँव-भूप भैरो, थाना-सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी, अनुक्रमांक 21503865
4. विजय कुमार, पुत्र-अशरफी रे, निवासी-गाँव-खपुरा के निवासी, डाकघर और थाना-खानपुर पाकरी, जिला-वैशाली, अनुक्रमांक 21511011
5. बिपिन कुमार, पुत्र- मथुरा प्रसाद, निवासी-गाँव-खाखरा, थाना-शेखपुरा, जिला-शेखपुरा, अनुक्रमांक 21512292
6. ललन कुमार, पुत्र- मुंड्रिका प्रसाद यादव, निवासी-गाँव- जैनगर बारी कवैगा, थाना-लखीसराय, जिला-लखीसराय, अनुक्रमांक 21504710
7. शशि भूषण कुमार, पुत्र- माधव प्रसाद यादव, निवासी-गाँव-राही जगतपुर, थाना-लक्ष्मीपुर लालचंद, जिला-मधेपुरा, अनुक्रमांक 21502683

8. रविंदर कुमार, पुत्र-वकील सिंह निवासी-गाँव-राजपुर, थाना-राजपुर, जिला-रोहतास, अनुक्रमांक-21505435 ।
9. संजय कुमार, पुत्र-स्वर्गीय श्याम किशोर सिंह, निवासी-गाँव -महथिन तोला, डाकघर और थाना-बालिगिरवन, जिला भोजपुर, अनुक्रमांक 21504660
10. नंदन सिंह, पुत्र- जवाहर सिंह, निवासी-गाँव-जमुराहा, थाना-रामगढ़, जिला कैमूर, अनुक्रमांक 21502502
11. सुशील कुमार यादव, पुत्र-दीपक कुमार निवासी-गाँव कुशाहा, डाकघर- कमलदह, थाना-किशनपुर, जिला सुपौल, अनुक्रमांक 21506290
12. अंशु कुमार, पुत्र-आनंद शिव नारायण सिंह, निवासी-गाँव-रतनपुर, थाना-बरियारपुर, जिला मुंगेर, अनुक्रमांक 21503758
13. कुमार बीरेंद्र सिंह, पुत्र- नवल किशोर सिंह, निवासी-गाँव-शेरपुर, डाकघर नेहुसा, थाना-हरनौत, जिला नालंदा, अनुक्रमांक-21508055
14. उमेश प्रसाद सिंह, पुत्र- स्वर्गीय भागवत सिंह, निवासी- गाँव-बिशुनपुर बेदौलिया, थाना-जंदाहा, जिला-वैशाली, अनुक्रमांक- 21509314
15. धनंजय कुमार यादव, पुत्र-सुरेश यादव, निवासी-आजाद नगर के निवासी, रोड संख्या-3 थाना कंकडबाग, जिला- पटना, अनुक्रमांक 21510343

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना अपने सचिव के माध्यम से।
2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के अध्यक्ष।
3. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के सचिव।
4. हंसराज हंस, पुत्र- रामसेवक सिंह, निवासी-गाँव-सोमनाहा मठ, थाना-पूसा, जिला-समस्तीपुर, अनुक्रमांक 21513082
5. मनोज कुमार, पुत्र- राम बदन चौधरी, निवासी-गाँव- गमरियां, थाना-नोखा, जिला-रोहतास, अनुक्रमांक 21512974
6. अमित कुमार, पुत्र- अशोक कुमार चकरवती, निवासी-गाँव रामदिहा, थाना-राहुई, जिला नालंदा, अनुक्रमांक 21510622
7. मनोज कुमार अकेला, पुत्र- राजेंद्र प्रसाद अकेला, निवासी-गाँव- नानंद, थाना-सिलाव, जिला नालंदा, अनुक्रमांक 21509910
8. अभिषेक प्रसाद, पुत्र- प्रदीप कुमार साह, निवासी-गाँव-हाफला गंज, डाकघर, थाना सिरनिया, जिला कटिहार, अनुक्रमांक 21504108
9. अमित कुमार, पुत्र-स्वर्गीय भारत भूषण प्रसाद, निवासी-गाँव जलालपुर, थाना-सोहसराय, जिला नालंदा, अनुक्रमांक 21500334

10. आनंद कुमार, पुत्र- राम बदन प्रसाद निवासी- सेंट्रल रेवेन्यू कॉलोनी, टाइप-**III**, क्वार्टर प्र. सं. 49, थाना-दीघा, जिला पटना, अनुक्रमांक 21513795
11. बिपू कुमार प्रसाद, पुत्र- हरहंगी प्रसाद, निवासी-गाँव- तिवारी चापड़ा, डाकघर, थाना भथवा.जिला- गोपालगंज, अनुक्रमांक 21500029
12. स्वर्ण किरण कुमार, पुत्र- नवल किशोर प्रसाद, निवासी-गाँव- केवल बीघा, घंघ, डाकघर, थाना सैस्तापुर, जिला पटना, अनुक्रमांक 21501110
13. रवि कुमार, पुत्र- शंकर लाल साह, निवासी- दुर्गा स्थान कस्बा, थाना-कस्बा, जिला-पूर्णिया, अनुक्रमांक 21502813
14. निशांत कुमार, पुत्र- मथुरा प्रसाद केशरी, निवासी- ग्राम- मधुबानी बाजार, प्रेमा इलेक्ट्रिकल, थाना- के. हाट जिला-पूर्णिया, पूरब, अनुक्रमांक 21510378
15. सुरेश गिरि, पुत्र- स्वर्गीय बिंदेश्वरी गिरी, निवासी-गाँव-खुशारा, थाना-कल्याणपुर, जिला-पूर्वी चंपारण, अनुक्रमांक 21510495
16. चंद्रशेखर कुमार, पुत्र- भिखारी महतो, निवासी-गाँव- राजवाड़ा बिरता, डाकघर मुशामिया, वाया सोनबरसा, थाना-मुशरनिया, जिला सीतामढ़ी
17. निदेशक, कृषि, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
18. निदेशक, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना।
19. निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, कृषि विभाग, पटना।
20. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना।

.... उत्तरदातागण

==========

रूपः

(2023 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 519 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता
		प्रिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री सर्वेश कुमार सिंह, अपर महाधिवक्ता-13
बी. एस. एस. सी. के लिए	:	श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
		श्री अभिषेक आनंद, अधिवक्ता
		सुश्री कनुप्रिया, अधिवक्ता,
		सुश्री सुष्मिता शर्मा, अधिवक्ता

(2023 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 520 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता
		प्रिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री सर्वेश कुमार सिंह, अपर महाधिवक्ता 13

बी. एस. एस. सी. के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
श्री अभिषेक आनंद, अधिवक्ता
सुश्री कनुप्रिया, अधिवक्ता
सुश्री सुष्मिता शर्मा, अधिवक्ता

==========

कोरमःमाननीय मुख्य न्यायाधीश
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय

सीएवी निर्णय

(द्वाराः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीखः12-01-2024

आरक्षण का जटिल सवाल और इसे 50 प्रतिशत तक सीमित रखने का जनादेश, ताकि योग्यता से समझौता न किया जा सके, इस विषय वास्तु को यहां उठाया गया है। मामले के तथ्यों पर इस सिद्धांत को लागू करने के परिणामस्वरूप मेधावी आरक्षित उम्मीदवारों (संक्षिप्तता के लिए, 'एमआरसी') को उनकी पसंद के जिले दिए गए; केवल उनकी उच्च योग्यता के कारण सक्षम किया गया, जिससे आरक्षित उम्मीदवारों को परिणामी रिक्तियों में मेधावी सामान्य उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए हटा दिया गया।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों, एक सार्वजनिक रोजगार में भर्ती के मामले में और दूसरा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में, पर अपीलार्थी और उत्तरदाता द्वारा क्रमशः अपने प्रतिद्वंदी विवादों का समर्थन करने के लिए भरोसा किया गया था। अपीलार्थी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संक्षिप्तता के लिए, 'बी. एस. एस. सी.') शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सेवा में नियुक्ति के रूप में अंतर का दावा करता है; जबकि उत्तरदाता-आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, जिन्हें 'एम. आर. सी.' उम्मीदवारों के आरक्षण पदों पर होने के कारण चयन सूची से बाहर कर दिया

गया था, दावा करते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में लागू सिद्धांत पूरी तरह से यहां लागू होता है, हालांकि यह लोक सेवा के लिए एक नियुक्ति है।

3. दोनों पक्षों द्वारा जिन दो अलग-अलग निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे हैं- ***रितेश आर. साह बनाम वाई. एल. यमुल (डॉ.), (1996) 3 एस. सी. सी. 253, त्रिपुरारी शरण बनाम रंजीत कुमार यादव, (2018) 2 एस. सी. सी. 656, डेगा वेंकट हर्ष वर्धन बनाम अकुला वेंटका हर्षवर्धन, (2019) 12 एस. सी. सी. 735*** शामिल है। शैक्षणिक संस्थानों और ***भारत संघ में प्रवेश बनाम रमेश राम, (2010) 7 एस. सी. सी. 234,*** एक संविधान पीठ ***आलोक कुमार पंडित बनाम असम राज्य*** के निर्णय के बाद, ***(2012) 13 एस. सी. सी. 516***, सिविल सेवाओं में नियुक्ति से संबंधित है।

4. निष्कासित 93 उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने कृषि निदेशक द्वारा 'बी.एस.एस.सी' के सचिव को संबोधित करते हुए जिलेवार आवंटन पत्र अभिलेख में लाया और परिणामी नियुक्ति के लिए 93 उम्मीदवारों की सिफारिश मांगी गई। यह सामान्य प्रशासन विभाग के एक पत्र पर आधारित था, (संक्षिप्तता के लिए, 'जी. ए. डी.') जिसमें पाया गया कि जब 'एम. आर. सी.' उम्मीदवारों को उनके वैकल्पिक जिलों में समायोजित किया जाता है, तो परिणामी रिक्ति आरक्षित उम्मीदवार को दी जानी चाहिए, जिसे वह पद मिलता जिसमें 'एम. आर. सी.' उम्मीदवार नियुक्त किया जाता है, जो चिकित्सा शिक्षा में नियोजित प्रथा थी। कृषि विभाग को एक अलग रास्ता अपनाने के लिए फटकार लगाई गई और उसी सिद्धांत का पालन करने का निर्देश दिया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस संचार को देखा; जिसने याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का निवारण किया और रिक्त पदों के लिए सिफारिशें करने का निर्देश दिया। रिट याचिका में फैसले से एक अपील दायर की गई थी, जिसमें आवश्यक होने पर समीक्षा दायर करने का निर्देश था।

5. विद्वान महाधिवक्ता के कार्यालय से एक कानूनी राय के आधार पर, 'जी. ए. डी.' ने अपना रुख बदल दिया, जिसके कारण 'बी. एस. एस. सी.' ने एक समीक्षा दायर की, जिससे दीवानी समीक्षा मामलों में आक्षेपित आदेश दिया गया। समीक्षा इस आधार पर मांगी गई थी कि जब एम. आर. सी. उम्मीदवार अपनी समग्र योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी के लिए अनुशंसित, लेकिन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के भीतर योग्यता के आधार पर एक विकल्प पद या पोस्टिंग प्राप्त करने के लिए एक विकल्प का प्रयोग किया है, तो आरक्षण रिक्ति को किए गए विकल्प के आधार पर समायोजित किया जाना है, जिसके परिणामस्वरूप रिक्तियों को सामान्य योग्यता के लिए स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार, एक एम. आर. सी. उम्मीदवार द्वारा प्रयोग किए गए एक विकल्प पर, यदि उसे आरक्षित श्रेणी के लिए अलग रखे गए एक विकल्प पद पर स्थानांतरित किया जाता है, तो ऐसे आरक्षण पद पर 'एम. आर. सी.' उम्मीदवार का कब्जा होता है। हालांकि, यदि 'एमआरसी' उम्मीदवार द्वारा इस तरह के विकल्प का उपयोग नहीं किया जाता है और उसे केवल उसकी योग्यता के आधार पर तैनात किया जाता है, तो कम योग्यता वाला आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार आरक्षण पद पर कब्जा करने का हकदार होगा। यह आरक्षण के अधिदेश के अनुरूप भी होगा जो एक समय में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जैसा कि संविधान पीठ द्वारा निर्धारित किया गया है। ***इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ*** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय; ***1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217।***

6. समीक्षा में ***रमेश राम (उपरोक्त)*** पर भरोसा करते हुए, बाद में 'जी. ए. डी.' द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को बरकरार रखा गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि समीक्षा झूठ नहीं हो सकती है, विशेष रूप से समीक्षा अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा को देखते हुए, लेकिन चूंकि जो मांगा गया था वह केवल एक स्पष्टीकरण के अनुसार की प्रकृति में था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि पहले के आदेश में केवल

उम्मीदवारों की अनुशंसा का निर्देश दिया गया था, जिसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि आरक्षित श्रेणी के उन 93 उम्मीदवारों की अनुशंसा की जानी थी, जिन्हें नियुक्ति के लिए विचार से बाहर कर दिया गया था। यह उक्त आदेश के खिलाफ है कि अपील 93 निष्कासित आरक्षित उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई है।

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मृगांक मौली ने मामले में उत्पन्न तथ्यों को इंगित करने के बाद तर्क दिया कि कृषि समन्वयक पद, जिस पद पर विषय चयन शुरू किया गया था, का विज्ञापन राज्यवार रिक्ति के आधार पर किया गया था। उम्मीदवारों को विशिष्ट जिलों को चुनने के लिए विकल्प दिए गए थे, क्योंकि रिक्तियों को प्रत्येक जिले से उत्पन्न होने के आधार पर अधिसूचित किया गया था। एक सामान्य योग्यता सूची तैयार की गई थी जिसमें आरक्षित उम्मीदवार जो योग्यता में उच्च थे, उन्हें सामान्य योग्यता में ही समायोजित किया गया था। हालाँकि, जहाँ तक जिलों के लिए किए गए विकल्पों की बात है, जब एक एमआरसी उम्मीदवार एक जिले में आरक्षित रिक्ति का हकदार था, जिसमें उसने एक विकल्प का प्रयोग किया था, तो उसे ऐसे आरक्षित रिक्ति में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह उक्ति के साथ संघर्ष करता है। ***रितेश आर. साह*** (उपरोक्त) और ***त्रिपुरारी शरण*** (उपरोक्त), ***रमेश राम*** (उपरोक्त) का कथन पूरी तरह से अलग परिस्थिति पर है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक रोजगार में नियुक्ति पर इतना अंतर नहीं है, बल्कि ***रमेश राम*** (उपरोक्त) में लागू सिद्धांत के अनुसार विभिन्न सेवाओं के संबंध में स्थिति की कोई पहचान नहीं है, जिनमें नियुक्तियां की गई थीं।

8. ***त्रिपुरारी शरण*** (उपरोक्त) में स्थिति की एक पहचान थी क्योंकि एक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश किया जा रहा था और विकल्प केवल उन संस्थानों में लागू किए जा रहे थे जिनमें इस तरह के प्रवेश किए जाते हैं। पहले मामले में, स्थिति में असमानता को देखते हुए, जहां तक विभिन्न सेवाओं का संबंध है, यह माना गया

था कि एम. आर. सी. से आरक्षण पद में उच्च सेवा में आरक्षित रिक्ति की ओर बढ़ने के परिणामस्वरूप ऐसी आरक्षित रिक्ति पर कब्जा कर लिया जाएगा। जबकि, जब स्थिति की पहचान होती है, तो एक पसंदीदा संस्थान का चयन केवल योग्यता के आधार पर 'एमआरसी' उम्मीदवार को एमआरसी में ही माना जा सकता है और किसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के अधिकार को दूसरे संस्थान में नियुक्त होने से वंचित नहीं कर सकता है। शैक्षणिक संस्थानों में लागू सिद्धांत सही आरक्षण सिद्धांत सुनिश्चित करता है और इससे 50% किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं होता है। एम. आर. सी. उम्मीदवार को आरक्षित रिक्ति में स्थानांतरित करने से योग्यता पर कोई समझौता नहीं होता है और वह सामान्य योग्यता के आधार पर भर्ती/नियुक्त उम्मीदवार बना रहता है, जबकि आरक्षित उम्मीदवार को किसी अन्य रिक्ति में नियुक्त किया जाएगा। यह केवल एम. आर. सी. उम्मीदवार की तुलना में कम योग्यता वाले आरक्षित उम्मीदवार को पसंदीदा पदस्थापना/संस्थान प्राप्त करने की अवैधता को दूर करता है। यह इंगित किया गया है कि अन्यथा सकारात्मक कार्रवाई की हताशा होगी।

9. विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें कृषि विभाग के संचार के माध्यम से अनुलग्नक-4 के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे कृषि विभाग और 'जी. ए. डी.' की संयुक्त बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर भी कहा गया था, जिसे अनुलग्नक-7 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ***त्रिपुरारी शरण*** (उपरोक्त) के आधार पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया था। रिट याचिका का निपटान भी ऐसे निर्णय के आधार पर किया गया था जो केवल महाधिवक्ता के कार्यालय से दी गई कानूनी राय पर नाराज था, जिसे अनुलग्नक-7 के साथ भी पेश किया गया है। यह इंगित किया गया है कि कानूनी राय गलत है।

10. शुरुआत में 'बी. एस. एस. सी.' की ओर से पेश विद्वान वकील श्री सत्यबीर भारती का तर्क है कि जहाँ तक जिला संवर्ग समन्वयकों के पद का संबंध है।

उन्होंने कैडर नियमों और उम्मीदवारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जिलों के चयन के लिए प्रदान किए गए विशिष्ट विकल्प पर भी भरोसा किया जो कैडर नियमों से भी निकलता है। यह बताया गया है कि यदि 'एम. आर. सी.' उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के कारण आरक्षित रिक्तियों में स्थानांतरित किया जाता है, तो आवश्यक रूप से, वे आरक्षण पदों पर कब्जा कर लेंगे और यदि उस रिक्ति में कोई अन्य आरक्षित उम्मीदवार नियुक्त किया जाता है जिसके लिए 'एम. आर. सी.' उम्मीदवार पात्र था, तो इसके परिणामस्वरूप योग्यता से समझौता होगा और योग्यता रखने वाले सामान्य उम्मीदवार को योग्य नियुक्ति प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। यह ***इंदिरा साहनी*** (उपरोक्त) के एक अन्य संविधान पीठ के फैसले में निर्धारित 50 प्रतिशत नियम का भी उल्लंघन करेगा। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति जैसे निर्णयों पर भरोसा किया जाता है, उनमें अंतर बताया जाता है। वर्तमान मामले में, लोक सेवाओं में नियुक्ति के संबंध में निर्णय पूरी तरह से लागू होंगे और ***रमेश राम*** (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांत से कोई विचलन नहीं हो सकता है।

11. विज्ञापन दिनांक 29.04.2015, में अनुलग्नक-1 के रूप में प्रस्तुत किया गया। 2020 का दीवानी पुनरीक्षण संख्या 21 के लिए कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के तहत कृषि समन्वयकों के रिक्त पदों पर भर्ती बुलाया गया। अधिसूचित कुल रिक्तियां 4391 थीं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़े वर्ग/पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए प्रत्येक आरक्षण श्रेणी के लिए पात्र रिक्तियों की संख्या भी निर्दिष्ट की गई थी। हमें तुरंत ध्यान देना होगा कि वर्तमान मामले में उठाया गया एकमात्र मुद्दा बी. सी. उम्मीदवारों के संबंध में है। 4391 रिक्तियों में से 3507 को नियुक्त किया गया है। पदों पर लागू आरक्षण का एक सारणीकरण पैराग्राफ संख्या 5 से देखा जा सकता है। 2020 का दीवानी पुनरीक्षण संख्या 21हमें अन्य

आरक्षण श्रेणियों के उम्मीदवारों को संदर्भित करने और केवल सामान्य और पिछड़े समुदाय के उम्मीदवारों के रूप में आंकड़ों को देखने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य श्रेणी में 2205 रिक्तियां थीं और 2169 उम्मीदवार विचाराधीन क्षेत्र में थे। अंतिम सिफारिश, जो कि जिलेवार थी, 1955 में की गई थी, जिसमें से 214 उम्मीदवार 'एमआरसी' उम्मीदवार थे। उनके द्वारा चुने गए जिलों के आधार पर, उन्हें पसंदीदा जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्हें केवल ऐसे जिलों के आरक्षित रिक्तियों में स्थानांतरित किया जा सकता था।

12. इस प्रकार चयनित जिलों में स्थानांतरित किए गए 214 एम. आर. सी. उम्मीदवारों में से 103 पिछडे वर्ग श्रेणी के उम्मीदवार थे। पिछडी जाति श्रेणी में 10 रिक्तियां खाली रह गई थीं, जिनमें 'एम. आर. सी.' उम्मीदवारों को विकल्पों के अभ्यास के अनुसार तैनात किया गया था। शेष 93 एम. आर. सी. उम्मीदवारों को भी उनके विकल्पों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों में तैनात किया गया था, जिन्हें आरक्षित पदों को भरने वाला माना गया था, इस प्रकार उक्त 93 पदों को सामान्य श्रेणी में स्वीकार कर लिया गया ताकि 50 प्रतिशत नियम का उल्लंघन न हो। परिणामस्वरूप, पिछडी जाति की आरक्षित श्रेणी के 93 व्यक्तियों को विभिन्न जिलों में आरक्षित रिक्तियों में 'एम. आर. सी.' उम्मीदवारों के समायोजन के कारण नियुक्ति के लिए विचार से बाहर कर दिया गया था, जिसमें 'एम. आर. सी.' उम्मीदवारों ने चुना था।

13. हम अपने सामने रखे गए निर्णयों से गुजरे हैं। तथ्य इंगित करते हैं कि तथ्यों पर निर्णयों के दो समूह, पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश और सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के संदर्भ में थे; लेकिन अंतर केवल उक्त तथ्यों पर नहीं है। अंतर्निहित सिद्धांत को ऐसे प्रवेशों या सेवाओं द्वारा प्रदान की गई स्थिति के आधार पर अलग किया जा सकता है; क्या नियुक्तियों/प्रवेशों में स्थिति की पहचान है या सेवाओं या पाठ्यक्रमों में असमानता है जिसमें नियुक्तियां और प्रवेश किए जाते हैं। जब 'एम.

आर. सी.' उम्मीदवारों को उनके विकल्पों के आधार पर आरक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाता है, तो कौन से विकल्प उस सेवा की स्थिति को भौतिक रूप से नहीं बदलते हैं जिसमें उन्हें नियुक्त किया जाता है; उन्हें आरक्षण रिक्तियों पर कब्जा करने वाला नहीं माना जा सकता है, इस प्रकार आरक्षण श्रेणी में कम योग्य उम्मीदवारों को ऐसे एमआरसी उम्मीदवार द्वारा खाली किए गए पद पर कब्जा करने से वंचित कर दिया जाता है। हालांकि, जब स्थिति में असमानता होती है, तो अनिवार्य रूप से आरक्षित रिक्ति में भर्ती या नियुक्त 'एमआरसी' उम्मीदवार को आरक्षण उम्मीदवार माना जाएगा, इस प्रकार आरक्षण श्रेणी में कम मेधावी उम्मीदवार को हटा दिया जाएगा और परिणामी रिक्ति को सामान्य योग्यता वाले उम्मीदवार को स्वीकार कर लिया जाएगा।

14. हमारी राय में, यह वह अंतर है जो हमारे सामने रखे गए उद्धृत निर्णयों से उत्पन्न होता है। ***रितेश आर. साह*** (उपरोक्त) एक ऐसा मामला था जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्या एक एमआरसी उम्मीदवार, जिसे उसकी पसंद के कॉलेज में आरक्षित रिक्ति में समायोजित किया जाता है, को आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित कोटे के खिलाफ गिना जाना चाहिए या उसे सामान्य उम्मीदवार के रूप में माना जाना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब किसी उम्मीदवार को अपनी योग्यता के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश दिया जाता है तो इस तरह के प्रवेश को आरक्षण कोटे के खिलाफ नहीं गिना जाना चाहिए। यह निर्णय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के संदर्भ में दिया गया था और इस सिद्धांत को पैराग्राफ 17 में उल्लेख किया गया जिसका ***रमेश राम*** (उपरोक्त) में निकाला गया हिस्सा इस प्रकार हैः-

"17. ... उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा

प्रतिपादित कानूनी स्थिति को देखते हुए यह निष्कर्ष अटूट है कि एक छात्र जो योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने का हकदार है, हालांकि वह आरक्षित श्रेणी से संबंधित है, उसे आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों के खिलाफ प्रवेश नहीं माना जा सकता है। लेकिन साथ ही प्रावधान इस तरह से किए जाने चाहिए कि यह ऐसे उम्मीदवार के लिए नुकसानदेह न हो और उसे अन्य कम मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक नुकसानदेह स्थिति में न रखा जाए। उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का पता लगाने के बाद जो अन्यथा खुली योग्यता सूची में आते हैं और फिर विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश के लिए उनका विकल्प पूछते हैं जिन्हें आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित रखा गया है और उसके बाद कम मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के मामलों पर विचार किया जाना चाहिए और उन्हें उन कॉलेजों में सीटें आवंटित की जानी चाहिए जहां सीटें उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जबकि अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश के हकदार एक आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास उन कॉलेजों में प्रवेश लेने का विकल्प होगा जहां आरक्षित श्रेणी के लिए निर्दिष्ट संख्या में सीटें आरक्षित रखी गई हैं, लेकिन आरक्षण के प्रतिशत की गणना करते समय उसे एक खुली श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में भर्ती

किया गया माना जाएगा, न कि आरक्षित श्रेणी उम्मीदवार।

15. उपरोक्त भाग को निकालने के बाद, ***रमेश राम*** (उपरोक्त) ने पैराग्राफ-32 में ऐसा कहाः-

"32. मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अर्हता प्राप्त करने और यूपीएससी परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने के बीच एक स्पष्ट अंतर है क्योंकि बाद की परीक्षा विभिन्न सिविल सेवाओं में रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जाती है। पहले मामले में, सभी सफल उम्मीदवारों को एक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने का समान लाभ मिलता है। हालांकि, बाद के मामले में सफल उम्मीदवारों को मिलने वाले लाभों में भिन्नताएं हैं क्योंकि वे अपनी पसंद की सेवा को सुरक्षित करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश उम्मीदवार प्राथमिकताओं के लिए पूछे जाने पर पहली तीन सेवाओं [यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई. ए. एस.), भारतीय विदेश सेवा (आई. एफ. एस.) और भारतीय पुलिस सेवा (आई. पी. एस.)] में से कम से कम एक का विकल्प चुनते हैं। अधिकांश उम्मीदवार पहले विकल्प के रूप में आई. ए. एस. को पसंद करते हैं। इस संबंध में,

> एक आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार जो सामान्य सूची के हिस्से के रूप में अर्हता प्राप्त कर चुका है, उसे सामान्य श्रेणी में रिक्तियों के मुकाबले निचली सेवा में नियुक्त किए जाने से वंचित नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि अगर उसने अपने आरक्षित श्रेणी के दर्जे का लाभ उठाया होता, तो उसे उच्च वरीयता की सेवा मिलती। इस तरह की विसंगति को रोकने के स्पष्ट इरादे के साथ, नियम 16 (2) में प्रावधान है कि एक एमआरसी उम्मीदवार सामान्य कोटा या संबंधित आरक्षित श्रेणी कोटा के बीच चयन करने की स्वतंत्रता। "

16. ***रमेश राम*** (उपरोक्त) एक ऐसा मामला था जिसमें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों में तीन अखिल भारतीय सेवाओं, पंद्रह समूह-ए सेवाओं और तीन समूह-बी सेवाओं के चयन को चुनौती दी गई थी। नियमों में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि आवंटन करते समय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों (क्रमशः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है, यदि इस प्रक्रिया से उन्हें अपनी पसंद के क्रम में उच्च पसंद की सेवा मिलती है। इस प्रकार, नियम 16 (2) ने किसी भी आरक्षित श्रेणी में मेधावी उम्मीदवार को उच्च वरीयता की सेवा प्राप्त करने में सक्षम बनाया ताकि उसे उसी आरक्षित श्रेणी के अन्य उम्मीदवारों की तुलना में नुकसानदेह स्थिति में नहीं रखा जा सके। उक्त प्रपत्र में नियम को 04.12.2004 को संशोधित किया गया था, जिसके पहले इस तरह के समायोजन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को कम योग्यता वाले उम्मीदवार को कम दर्जे की सेवा में चयन के लिए विचार करने से

वंचित नहीं करेंगे; यदि 'एम. आर. सी.' उम्मीदवार का समायोजन आरक्षित रिक्ति में किया जाता है।

17. जैसा कि उपरोक्त उद्धरण [***रमेश राम*** (उपरोक्त) के पैराग्राफ-32] में देखा गया है कि ***रितेश आर.साह*** (उपरोक्त) से तथ्यों पर अंतर यह था कि पहले का मामला एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से संबंधित था और बाद वाला विभिन्न सिविल सेवाओं में रिक्तियों को भरने के लिए था। इस बात पर जोर दिया गया कि पहले मामले में, सभी सफल उम्मीदवारों को एक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने का समान लाभ प्राप्त होता है जो एक योग्यता की ओर ले जाता है, जिससे चिकित्सा में अभ्यास करने में सक्षम होता है; जहां स्थिति की पहचान होती है और किया गया समायोजन केवल किसी विशेष कॉलेज में 'एमआरसी' उम्मीदवार द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प की प्रकृति में होता है। यह विकल्प विभिन्न कारकों पर आधारित हो सकता है, जैसा कि हम देखते हैं; इलाके में अधिवास, गृहनगर से आसान पहुंच और यहां तक कि अधिक प्रतिष्ठित संस्थान प्राप्त करने के लिए; लेकिन सभी एमबीबीएस की समान योग्यता की ओर ले जाते हैं।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न सिविल सेवाओं में नियुक्तियों के संबंध में एक अलग रास्ता अपनाते हुए विशेष रूप से ध्यान दिया कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा समूह-ए और समूह-बी पदों के लिए चयन में, उन सफल उम्मीदवारों को मिलने वाले लाभों में असमानता है जो अपने पसंद की सेवा प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से ध्यान दिया कि एक एम. आर. सी. उम्मीदवार को उसकी योग्यता के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति की अनुमति दी जाएगी, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा में उसके विकल्प के आधार पर, उसे उस सेवा में आरक्षित रिक्ति में समायोजित किया जा सकता है। नियम इस तरह के समायोजन की अनुमति देता है लेकिन इसके

परिणामस्वरूप 'एमआरसी' उम्मीदवार को आई. ए. एस. में आरक्षित रिक्ति में नियुक्त माना जाता है। अन्यथा, यदि योग्यता-आधारित आवंटन, प्रयोग किए गए सेवा के विकल्प के आधार पर नहीं किया जाता है, तो 'एम. आर. सी.' उम्मीदवार को आई. पी. एस. में नियुक्त किया जाएगा, हालांकि उनका पहला विकल्प आई. ए. एस. था, जबकि एक अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, जिन्होंने समान विकल्प बनाया था, उन्हें 'एम. आर. सी.' उम्मीदवार की तुलना में कम योग्यता होने के बावजूद, आई. ए. एस. में आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए सक्षम किया जाएगा। इस तरह की विसंगति और अनावश्यक नाराज़गी को दूर करने के लिए, विशेष रूप से अलग-अलग लाभ और अलग स्थिति वाली विभिन्न सेवाओं के संदर्भ में, नियम इस तरह से बनाया गया था, ताकि एक आरक्षित रिक्ति में समायोजन किया जा सके; एक एमआरसी उम्मीदवार, एक उच्च या बेहतर सेवा में, जिसे आरक्षित श्रेणी में से एक माना जाता है। नियुक्ति की स्थिति में असमानता और किसी विशेष सेवा में बाद में अवशोषण के अनुमान पर उपरोक्त नियम बनाया गया था।

19. ***रमेश राम*** (उपरोक्त) के पैराग्राफ-35 में ऐसा माना गया थाः-

> "35. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए दो चरणों में सी. एस. ई. परिणाम घोषित करने के औचित्य पर सवाल उठाया कि भले ही एम. आर. सी. उम्मीदवारों को उच्च वरीयता की सेवा दी जाए, उन्हें निम्न श्रेणी के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को बाहर नहीं करना चाहिए। हालांकि, नियम 16 (2) की व्याख्या अलग तरीके से नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इसे एमआरसी उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए

बनाया गया था। एम. आर. सी. उम्मीदवार आवेदन के समय एससी/एसटी/ओ. बी. सी. के रूप में अपनी स्थिति का संकेत देते हैं, आरक्षित उम्मीदवारों के रूप में परीक्षा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी शुरू करते हैं। सामान्य योग्यता मानक के अनुसार अर्हता प्राप्त करने के बाद, उनके पास आरक्षित श्रेणी से बाहर निकलने और सामान्य पद पर कब्जा करने का अतिरिक्त विकल्प होता है। हालाँकि, जहाँ वे आरक्षित सूची में एक बेहतर पद प्राप्त करने में सक्षम हैं, सामान्य सूची में उनकी नियुक्ति उन्हें उससे वंचित नहीं करेगी। इस संबंध में, नियम 16 (2) में निर्दिष्ट समायोजन, वास्तव में, एम. आर. सी. की स्थिति में सामान्य से आरक्षित में किसी भी परिवर्तन को नहीं दर्शाता है। इसके विपरीत, यह एम. आर. सी. उम्मीदवार के आरक्षित दर्जे की पुष्टि है। एम. आर. सी. उम्मीदवारों की इस आरक्षित स्थिति की रक्षा के लिए नियम 16 (2) मौजूद है।

20. यह सच है कि ***देग वेंकट हर्ष वर्धन*** और ***त्रिपुरारी शरण*** (उपरोक्त दोनों) फिर से चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में थे, हालांकि, हमें ***त्रिपुरारी शरण*** (उपरोक्त) में कंडिका-16 पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जहां अदालत ने विशेष रूप से ***रमेश राम*** (उपरोक्त) का उल्लेख किया है, जिसमें ***रितेश आर. साह*** (उपरोक्त) का एक स्पष्ट रूप से विपरीत निर्णय आया था। पीजी उम्मीदवारों के चयन और नियुक्ति और यूपीएससी उम्मीदवारों के चयन और नियुक्ति के बीच अंतर बताया गया था। यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया था,“ जबकि स्नातकोत्तर प्रवेश में,

परिणाम सभी उम्मीदवारों को रैंक (यानी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश) की परवाह किए बिना समान लाभ प्रदान करेंगे, यूपीएससी चयन में परिणाम अलग-अलग रैंक धारकों को अलग-अलग लाभ देते हैं, क्योंकि सेवाओं का आवंटन इन रैंक के आधार पर होता है **(Sic)** विद्वान न्यायाधीशों ने भी कंडिका 17 में ऐसा कहाः

विद्वान न्यायाधीशों ने भी पैराग्राफ-17 में ऐसा कहाः-

> **"**17. यह भी ध्यान देने योग्य है कि जहां तक एक सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का संबंध है, संविधान पीठ ने रितेश आर. साह [रितेश आर. साह बनाम वाई. एल. यमुल, (1996) 3 एस. सी. सी. 253] को वस्तुतः लेकिन निहित रूप से मंजूरी दे दी है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित किए गए सिद्धांत रमेश राम (भारत संघ बनाम रमेश) राम (2010) 7 एस. सी. सी. 234:(2010) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 412] इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि यह मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से संबंधित मामला है और जबकि रमेश राम [भारत संघ बनाम रमेश राम, (2010) 7 एससीसी 234:(2010) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 412] यू. पी. एस. सी. परीक्षा के माध्यम से सेवाओं के लिए पदों के चयन से संबंधित है। **"**

21. ***आलोक कुमार पंडित*** (उपरोक्त) फिर से विभिन्न राज्य सेवाओं के लिए एक चयन और नियुक्ति थी, जो यू. पी. एस. सी. द्वारा की गई नियुक्ति के समान है, जो ***रमेश राम*** (उपरोक्त) में विचार का विषय था।

22. यह उपरोक्त संदर्भ में है और सैद्धांतिक रूप से विशिष्ट अंतर है न कि प्रवेश और नियुक्तियों के बीच अंतर पर, कि तत्काल मामले पर विचार किया जाना है।

23. तत्काल चयन कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के तहत कृषि समन्वयक के पद के लिए था। विज्ञापन की एक प्रति सिविल समीक्षा मामलों में अनुलग्नक-1 के रूप में प्रस्तुत की जाती है जिनसे अपीलें आती हैं। अधिवक्ता समूह में एक अनुवादित प्रति भी प्रस्तुत की गई थी। विज्ञापन इस तरह के आरक्षण के हकदार विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्र रिक्तियों की संख्या और आरक्षण कोटा को इंगित करता है। विभिन्न जिलों में रिक्तियों का विवरण देते हुए, विज्ञापन प्रत्येक जिले में कुल स्वीकृत पदों को इंगित करता है जिनमें से आरक्षण कोटा और सामान्य कोटा को अलग किया गया था और अलग से दिखाया गया था। यह वह संदर्भ है जिसमें उम्मीदवारों को 38 जिलों के संबंध में अपना विकल्प देना आवश्यक है। विज्ञापन में यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि जो उम्मीदवार अपना विकल्प नहीं देंगे, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार जिला आवंटित किया जाएगा। इसलिए, जैसा कि ***रमेश राम*** (उपरोक्त) में है, उन सेवाओं में लाभों में कोई असमानता नहीं है जिनके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उपयोग किया जाने वाला विकल्प सेवा के संबंध में भी नहीं है; जो वर्तमान मामले में केवल एक संवर्ग पद है, और विशेष रूप से जिले के आवंटन के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक पदों का संबंध है, कोई जिला संवर्ग नहीं है और विज्ञापन में दिए गए आरक्षण के तौर-तरीकों से यह संकेत नहीं मिलता है कि चयनित जिलों में 'एम. आर. सी.' उम्मीदवारों के लिए आरक्षण पद में कोई समायोजन

किया जा रहा है और इस प्रकार, कम योग्य आरक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए विचार करने से वंचित किया जा रहा है।

24. हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309; कृषि समन्वयक संवर्ग (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 2014 के तहत लाए गए संवर्ग नियमों की भी आपूर्ति की गई है। कृषि समन्वयक को ऐसे कार्मिक के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रखंड स्तर से नीचे कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं को लागू करने में तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग देते हैं; जिसे उसे राज्य संवर्ग बनाता है। रिक्तियों का निर्धारण जिलेवार किया जाता है और नियम स्वयं ही योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर नियुक्ति के लिए एक विकल्प प्रदान करते हैं, जो स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है वह नियम 16 (2) के समान एक नियम है, जिसे ***रमेश राम*** (उपरोक्त) के मामले में देखा गया था। वास्तव में, इस तरह के नियम की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिस पद पर नियुक्ति की जाती है, उसकी एक पहचान चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के समान होती है। जिला वार विकल्प नियुक्त व्यक्ति को उसके गृह जिले या उसके अधिवास जिले के पास के जिले में रहने के अलावा कोई अतिरिक्त लाभ नहीं देता है।

25. योग्यता सूची तैयार की गई और आरक्षण पद में स्थान पाने के हकदार उम्मीदवारों की एक सूची भी तैयार की गई, और फिर विकल्पों पर विचार किया गया। उच्च योग्यता वाले व्यक्ति को पहले अपने वैकल्पिक जिले के लिए माना जाएगा और यह उस संदर्भ में है कि 'एमआरसी' उम्मीदवार जिन्हें योग्यता के आधार पर कृषि समन्वयक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, उन्हें आरक्षित रिक्ति में उनके वैकल्पिक जिले में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो उन्हें राज्य की सेवा में कोई अतिरिक्त लाभ या कथित उच्च दर्जा नहीं देता है। यह सुविधा का एक नियम है ताकि एक मेधावी उम्मीदवार को सक्षम बनाने के लिए प्रयोग किए गए विकल्प के आधार पर एक अलग स्थिति वाली उच्च सेवा के लिए आवंटित किया जाता है, तो अपने

विकल्प का एक जिला प्राप्त करने के लिए योग्य उम्मीदवार, जिसके परिणामस्वरूप स्थिति अलग हो जाती है। यदि उस सेवा में स्थिति की पहचान की स्थिति में, जिसमें नियुक्ति की जाती है, आरक्षित रिक्ति को उसकी पसंद के जिले को आवंटित एमआरसी उम्मीदवार द्वारा भरा गया माना जाता है, तो यह आरक्षित श्रेणी से संबंधित 'एमआरसी' उम्मीदवार की योग्यता को समाप्त कर देगा। इसलिए, जब उस जिले के रूप में प्रयोग किए गए विकल्प के आधार पर एक काल्पनिक समायोजन किया जाता है, जहां तक नियुक्ति की जानी है, तो नियुक्ति का स्थानांतरण केवल 'एमआरसी' उम्मीदवार और कम योग्यता वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के खिलाफ होता है, जिस स्थिति में, कम योग्यता वाले आरक्षित उम्मीदवार को 'एमआरसी' उम्मीदवार के स्थानांतरण द्वारा बनाई गई रिक्ति पर विचार करना होगा। उपरोक्त तर्क पर, तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय है कि ***रमेश राम*** (उपरोक्त) में सिद्धांत लागू नहीं होगा और ***रितेश आर.साह*** और ***त्रिपुरारी शरण*** (उपरोक्त दोनों) में स्पष्ट रूप से लागू होगा।

26. हमारा मानना है कि 'एम. आर. सी.' उम्मीदवारों को उन जिलों में स्थानांतरित करके बनाई गई 93 रिक्तियां जिन्हें वे चुने गए उम्मीदवारों को उन आरक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए, वे उन वैकल्पिक जिलों में अस्थिर होंगे जहां उन्हें नियुक्त किया गया था। यद्यपि अनुलग्नक-7, सामान्य प्रशासन विभाग की प्रारंभिक राय और महाधिवक्ता की राय का संदर्भ दिया गया था, हमारा विचार है कि यह इसमें उठाये गए मुद्दे के निर्णय को विनियमित नहीं करता है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा भी नियंत्रित होता है। हमारी व्याख्या विभाग और विद्वान महाधिवक्ता की व्याख्या पर हावी होगी।

27. अपीलों को उपरोक्त निर्देशों के साथ अनुमति दी जाती है एवं पक्षकारों को अपनी-अपनी लागत वहन करने हेतु छोड़ा जाता है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

राजीव रॉय, न्यायमूर्ति: मैं सहमत हूँ।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

आदित्य/सुजीत/अनुष्का

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।